तिब्बत

और भारत की सुरक्षा

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज की ओर से जारी

चीनी आक्रमणकारियों ने तिब्बत को लूटा और उसकी शांतिप्रिय जनता को बर्बाद किया। सांस्कृतिक एंव धार्मिक रूप से तिब्बत भारत से ज्यादा निकट है। इसलिये हमें तिब्बत को चीन के खूनी पंजों से आजाद करवाकर तिब्बतियों को सौंपना होगा जिससे कि तिब्बती जनता स्वतंत्रता में मुक्त सांस ले सके।

- डॉ राजेंद्र प्रसाद, गांधी मैदान, पटना की जनसभा में,
24 अक्तूबर **1962**

तिब्बत के संबंध चीन की तुलना में भारत से ज्यादा मजबूत हैं। भारत और तिब्बत में भाषा, व्यापार और संस्कृति के संबंधो के अलावा खासकर पश्चिमी तिब्बत में सामरिक समानता है। इसलिए चीन की सरकार ने तिब्बत पर हमला बोलकर भारत के हितों पर भी चोट की है।

- डॉ० राम मनोहर लोहिया,
अक्तूबर, **1950**

MONGOLIA
BEIJING
EAST TURKISTAN
CHINA
TIBET
LHASA
AFGHANISTAN
PAKISTAN
NEPAL
DELHI
BANGLA DESH
MYANMAR (BURMA)

अपील

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़ पूरे भारत के 150 से अधिक तिब्बत समर्थक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वयं सेवी संगठन है। इन सभी संगठनों और भारत के लाखों तिब्बत-मित्रों की ओर से हम "तिब्बत और भारत की सुरक्षा" शीर्षक वाली यह पुस्तिका प्रस्तुत कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में कम से कम तीन महाद्वीपों के बड़े राष्ट्रों में जिस प्रकार संसदीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर पहलें हुई हैं वे तिब्बत के स्वतंत्रता अभियान के लिए बढ़ते हुए समर्थन का महत्वपूर्ण संकेत हैं।

परमपावन दलाई लामा जी का वह प्रस्ताव जिसमें तिब्बत को अहिंसा-क्षेत्र घोषित करने, उसकी अनूठी संस्कृति और धर्म का संरक्षण करने (जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ही विस्तार है) और तिब्बत को सैन्य एवं परमाणुविक रहित क्षेत्र में बदलने की बात कही गई है, वह भारत के राष्ट्रीय हित में है। हम संयुक्त राष्ट्र संध में अपनी सरकार के उस वक्तव्य का स्मरण करते हैं जिसमें उसने कहा था, "क्या हम उस भयानक त्रासदी के महज दर्शक मात्र बन कर रह सकते हैं जिसे अत्याचारी और दमनकारी सरकार द्वारा तिब्बत में खेला जा रहा है?"

हाल की घटनाओं पर नजर डालने से हम पाते हैं कि चीन सरकार और निर्वासित तिब्बती सरकार के बीच सम्पर्क सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहें हैं। परम पावन दलाई लामा जी के प्रस्तावों का समर्थन करना चीन के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि यह शांति और न्याय के पक्ष में हैं।

भारत के राष्ट्रीय हित और हाल के दिनों की घटनाओं को ध्यान में रखकर हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह परम पावन दलाई लामा जी के व्याहवारिक एंव रचनात्मक प्रस्तावों का समर्थन करे और यथासम्भव शीघ्र तिब्बत पर अपनी स्पष्ट नीति के आधार पर सक्रिय पहल करे।

डॉ० नन्दकिशोर त्रिखा
राष्ट्रीय संयोजक

श्री विजय क्रान्ति
राष्ट्रीय सह-संयोजक

डॉ० आनन्द कुमार
राष्ट्रीय सह-संयोजक

श्री कुलभुषण बक्शी
राष्ट्रीय सह-संयोजक

डॉ० कुलदीपचन्द अग्निहोत्री
राष्ट्रीय सह-संयोजक

तिब्बत पर भारतीय नेताओं के उद्‌गार

"जहाँ तक तिब्बत का प्रश्न है, इस समस्या के समाधान के लिये जो अच्छा से अच्छा उपाय हो सकता है, हमने उसे निकालने की कोशिश की है। श्री राजीव गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी चीन यात्रा के समय जो कुछ कहा गया था, हमने इस बार उसी पर जोर दिया है। तिब्बत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें तिब्बत स्वायत क्षेत्र भी हैं। लेकिन इस बात के बारे में विस्तार में जाने से एक नया विवाद खड़ा हो जायेगा।"

– श्री अटल बिहारी वाजपेयी,
राज्य सभा में प्रश्न का जवाब देते हुए।
(अगस्त, 2003)

तिब्बत के प्रति चिंता और जिम्मेदारियां इसलिए हैं कि वह हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ अन्याय किया गया है। यह जिम्मेदारी इस बात से बढ़ जाती है कि उसने हमारे आश्वासनों पर विश्वास किया है।

– श्री जय प्रकाश नारायण,
30 मई 1959

सचमुच में, जिन सिद्धांतो को मैं सर्वोच्च मानता हूं उनके अनुसार तिब्बत के बारे में आखिरी आवाज तिब्बत के लोगों की होनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं।

– पंडित जवाहर लाल नेहरू,
7 दिसम्बर, 1950
लोकसभा में

पंचशील बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण हिस्सों में है। अगर श्री माओ को पंचशील में रत्ती भर भी विश्वास होता तो वे अपने देश में बौद्धों के साथ अलग तरह से व्यवहार करते।

– डॉ० भीम राव अम्बेडकर,
1959 में संसद में पंचशील समझौते पर बहस में भाग लेते हुए

दलाई लामा जी चीन के साथ समझौता करने में सफल हों और हमारे प्रधानमंत्री इस संबंध में कोई मध्यस्थता कर सकें तो इससे बढ़ कर देश की जनता को कोई और आनन्द नहीं होगा। लेकिन, अगर चीन के नेताओं को सही राह पर नहीं लाया जा सकता, राजनीतिक या कूटनीतिक दबाव से उन्हें नहीं समझाया जा सकता तो भारत के सामने इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा कि हम दलाई लामा को अपने देश की आजादी के लिये संघर्ष करने की छूट दें ।

– श्री अटल विहारी वाजपेयी,
8 मई, 1959 लोकसभा में

तिब्बत में जो कुछ हुआ है, उसके प्रति हम लोग उदासीन नहीं हैं। लेकिन इस बारे में कुछ प्रभावशाली कर पाने की स्थिति में भी हम नहीं हैं।

प्रधानमंत्री
पं० जवाहर लाल नेहरू का
अंतिम पत्र जो उन्होंने डॉ०
गोपाल सिह के नाम लिखा,
24 मई, 1964

चीनी आक्रमणकारियों ने तिब्बत को लूटा और उसकी शांतिप्रिय जनता को बर्बाद किया। सांस्कृतिक एंव धार्मिक रूप से तिब्बत भारत से ज्यादा निकट है। इसलिये हमें तिब्बत को चीन के खूनी पंजों से आजाद करवाकर तिब्बतियों को सौंपना होगा जिससे कि तिब्बती जनता स्वतंत्रता में मुक्त सांस ले सके ।

– डॉ राजेंद्र प्रसाद, गांधी मैदान,
पटना की जनसभा में,
24 अक्तूबर 1962

तिब्बत का मुद्दा तिब्बत की सम्प्रभुता की कानूनी खोज का नहीं है। यह मानवाधिकारों का प्रश्न है। इसे न्याय और मानवता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, किसी कानूनी पहेली के रूप में नहीं।

– श्री सी० राजगोपालाचारी

तिब्बत के संबंध चीन की तुलना में भारत से ज्यादा मजबूत हैं। भारत और तिब्बत में भाषा, व्यापार और संस्कृति के संबंधो के अलावा खासकर पश्चिमी तिब्बत में सामरिक समानता है। इसलिए चीन की सरकार ने तिब्बत पर हमला बोलकर भारत के हितों पर भी चोट की है।

- डॉ० राम मनोहर लोहिया,
अक्तूबर, 1950

सांस्कृतिक तौर पर तिब्बत की चीन के मुकाबले भारत से ज्यादा निकटता है। मैं इसे (तिब्बत पर चीनी हमले को) वैसा ही उपनिवेशवादी अतिक्रमण मानता हूं जैसा किसी पश्चिमी राष्ट्र ने अन्यत्र किया हो।

- आचार्य जे० बी० कृपलानी, 8 मई, 1959 को लोकसभा में हुई बहस के दौरान

तिब्बत की स्वायत्तता हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे सुरक्षित नहीं करा सके तो न केवल हमारी अखंडता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी, बल्कि हमारे लिए गुटनिरपेक्षता की नीति जारी रखना भी असम्भव हो जायेगा।

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
27 अप्रैल, 1959

"तिब्बत में जो हो रहा है, वह बलात् सैनिक कब्जा और तिब्बतियों को गुलाम बनाना है। लोगों को जेलों में भरा जा रहा है, उनके मठ बर्बाद किये जा रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तिब्बत की जनता इस अपवित्र कब्जे से पीड़ित है।

- श्री एस० निजलिंगप्पा,
काग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
एंव पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक

....राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखे तो तिब्बत का इस तरह मिट जाना भविष्य में भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता।

- श्री अटल विहारी वाजपेयी,
17 मार्च, 1960 लोकसभा में

मेरे विचार से चीनियों की कार्यवाई विश्वासघात जैसी ही है। इस पर भी त्रासदी यह है कि तिब्बती जनता ने हम पर विश्वास किया। उन्हानें अपने मार्गदर्शन के लिये हमें ही चुना है। हम उन्हें चीनी कूटनीति के शिकंजे से मुक्त कराने में असफल रहे हैं।

- सरदार वल्लभ भाई पटेल
(तत्कालीन गृह मंत्री) द्वारा तत्कालीन
प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू
को लिखे पत्र का अंश,
7 नवंबर, 1950

तिब्बत की समस्या

एंव उसका भारत की सुरक्षा एंव आर्थिक खुशहाली पर सीधा प्रभाव

देशभक्त भारतीयों के लिये तिब्बत का प्रश्न सिर्फ तिब्बती जनता की दुर्दशा पर चिंतित होने तक ही सीमित नहीं है। भारत और तिब्बत के रिश्ते लिखित इतिहास से भी पुराने हैं। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आजाद तिब्बत भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तिब्बती जनता के लिये है।

'भारत-तिब्बत' सीमा से 'भारत-चीन' सीमा

सदियों से भारत और चीन के बीच कोई साझी सीमा नहीं रही। 1949 में चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तभी से वह भारत का पड़ोसी देश बन गया। तिब्बत शुरू से ही एशिया के तीन शक्तिशाली देशों भारत, चीन और सोवियत रूस के बीच बफ़र राज्य के रूप में स्थित रहा है। तिब्बत पर चीनी कब्जे से पहले भारत-तिब्बत की 3520 कि० मी० लम्बी सीमा विश्व की सबसे अधिक शांत सीमा के रूप में जानी जाती थी। सन् 1949 तक सिर्फ 75 पुलिस अधिकारी भारत तिब्बत सीमा के दक्षिणी भाग की रक्षा करते थे, और अब भारत को 7 से 8 डिवीज़न सेना को इसके के लिये स्थायी तौर पर रखना पड़ रहा है।

तिब्बत पर चीन के कब्जे से भारतीय अर्थव्यवस्था क्षीण हो रही है

तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से भारत और तिब्बत के बीच की सीमा एशिया की सबसे जबरदस्त किलाबन्द सीमा बन गयी है। इस कारण भारत को अपने आर्थिक साधनों को एक बड़ा हिस्सा विकास के बजाए इस सीमा पर खर्च करना पड़ रहा है। सिर्फ हिमालय की रक्षा के लिये भारत को हर रोज़ कई करोड़ रूपये खर्च करना पड़ता है। भारत-तिब्बत सीमा के भारत-चीन सीमा में बदलने के कारण होने वाले इस खर्च का भारत के ग्रामीण इलाकों के करोड़ों लोगों को स्वचछ जल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर खर्च किया जा सकता था। लेकिन यह तिब्बत के आज़ाद होने से ही संभव होगा।

चीन के भारत-विरोधी घोषित लक्ष्य

1949 में चीन के तत्कालीन अध्यक्ष माओ ने घोषणा की थी कि-''तिब्बत चीन की हथेली है और लदाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा उसकी अंगुलियां हैं।'' विश्व में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो बरसों तक सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता देने से इंकार करता रहा। बीजिंग से खुले-आम घोषणा की जाती है कि अरूणाचल प्रदेश (जो कि पहले नेफा के रूप में जाना जाता था) चीन का हिस्सा है। 26 सितम्बर, 1959 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चीनी प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के अनुसार भारत की चालीस हजार वर्ग किलोमीटर भूमि (अक्साईचिन, लद्दाख के पांगोंग और दमचोक, हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रा स्पीति दर्रा और नीलंग-जाधंग का क्षेत्र; उत्तर प्रदेश में बाड़ाहोती का क्षेत्र, तथा अरूणाचल प्रदेश में खिंजेमने, शात्से, लोंगचू एंव मिगितुन क्षेत्र) चीन के कब्जे में हैं।

चीन द्वारा पाकिस्तान का भारत के विरोध में उपयोग

यह संदेह से परे है कि चीन पाकिस्तान के नाभकीय कार्यक्रमों में तथा अरब सागर में ग्वादर पोर्ट में नौसैनिक अड्डा तैयार करने में भरपूर सहायता कर उसे भारत के विरोध में खड़ा होने के लिये मदद कर रहा है। इससे भारत का पूरे पश्चिमी तट के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा हो गया है। वास्तव में तिब्बत पर चीन का कब्जा होने से ही यह संभंव हुआ चीन पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल की ओर से भारत की घेराबंदी कर रहा है।

चीन का भारत के विरूद्ध बाजार-युद्ध

पिछले कुछ वर्षों में भारत के अनुभव से निसंदेह सिद्ध हो गया है कि चीन ने भारत के उद्योग एंव व्यापारिक समुदायों के खिलाफ बाजार युद्ध छेड़ रखा है। तिब्बत के रास्ते चीनी वस्तुओं की तस्करी तथा वैध निर्यात से भी भारत के हजारों उद्योग धंधे, विशेषकर खिलौना एंव इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं।

तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण

भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन के अनुसार सन् 2000 मे हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ से जो हानि हुई थी उसका कारण चीन द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़ना था जो तिब्बत के कृत्रिम एंव प्राकृतिक जलाशयों में इकट्ठा था। चीन द्वारा तिब्बत के जंगलों एंव खनिज पदार्थो को अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप भारत के असम राज्य और बांग्लादेश को हर साल भारी बाढ़ का सामना करना पडता है। इससे भारत की बहुत बडे पैमाने पर हानि हो रही है।

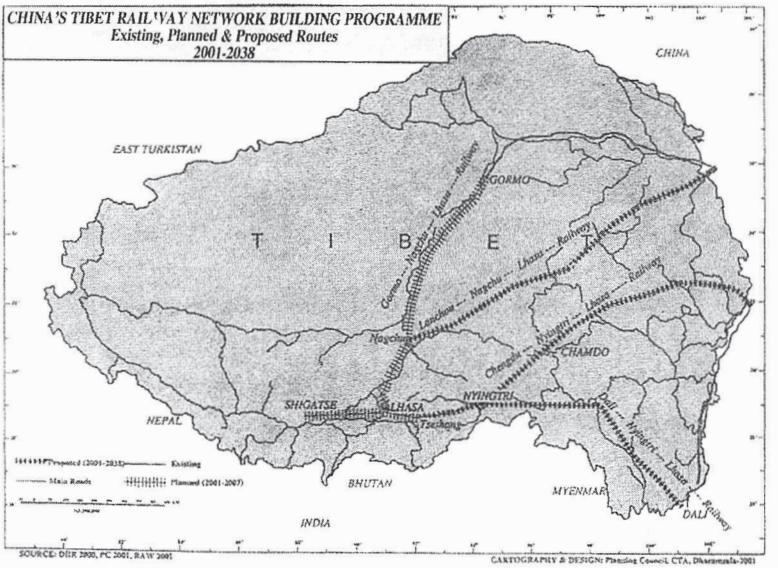

चीन की गोरमो से ल्हासा रेल लाइन बनाने की नयी योजनाः भारत की सुरक्षा के लिये स्थायी खतरा

रेल लाइन बनाने की इस योजना के संदर्भ में 10 अगस्त 2001 को न्यूयार्क टाइम्स को दिये साक्षात्कार में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने कहा था कि यह परियोजना एक राजनीतिक फैसला है। इसलिये किसी भी कीमत पर हम लोग इसे पूरा करेगें। अगर इसके लिये व्यावसायिक घाटा भी सहना पडे तो उसे सहेंगें। कूटनीतिज्ञों एंव विशेषज्ञों को विश्वास है कि गोरमो से ल्हासा तक रेल लाइन बिछाने से इस क्षेत्र में फैले असंतोष को कुचलने के लिये सैनिक पहुंचाने में आसानी होगी और इस क्षेत्र पर अपना सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिलेगी। साम्यवादी चीन द्वारा रेल विकास करने की दृढ इच्छा इस बात को दर्शाती है की भारी खर्च की परवाह किए बिना वह अपनी सैनिक शक्ति को प्राथमिकता दे रहा है।

रक्षा संतुलन में परिर्वतन

रेल लाइन बिछाने की इस परियोजना का 2007 में प्रथम चरण पूरा होते ही चीनी रक्षा सैनिकों के लिये भारतीय सीमा पर भारी अस्त्र शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री अति अल्प सूचना पर पहुंचाना संभव हो जायेगा। इससे भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा और खतरे में पड़ जाएगी।

विशाल सैनिक अड्डे के रूप में तिब्बत

आज तिब्बत में चीन के शास्त्रागार में 17 गुप्त रडार केन्द्र, कम से कम 8 अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों, मध्यम दूरी के 70 और कम दूरी वाले 20 प्राक्षेपास्त्र उपलब्धों से लैस आठ प्रक्षेपास्त्र अड्डे हैं । तिब्बत में तैनात कुछ प्राक्षेपास्त्रों की मारक दूरी 13,000 किमी है और वे एशिया की विभिन्न जगहों तक मार कर सकते हैं। रेल लाइन बन जाने से चीन के लिए तिब्बत को स्थायी सैनिक अड्डे में बदलना संभव हो जायेगा जहां से वह भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई कर सकेगा। वह पाकिस्तान और म्यांमार के जरिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक पहुँच सकेगा।

जनसंख्या स्थानांतरण

चीन सरकार द्वारा तिब्बत में चीनी जनसंख्या बसाने का अभियान रेल लाइन के बिछ जाने के बाद और अधिक तेज हो जायेगा। तब तिब्बत को चीन का स्थायी उपनिवेश बना दिया जायेगा। इस प्रकार चीन पूरे दक्षिणी एशिया, विशेषकर भारत के लिये स्थायी खतरा बन जायेगा। पहले ही तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बनाया जा चुका है। यह परियोजना मंचूरिया, सिंकियांग और मंगोलिया की कहानी को दोहराएगी।

धर्मशाला और बीजिंग

वार्ता की पहल

फरवरी 1979

बीजिंग में देंग सियाओ पिंग परम पावन दलाई लामा के बडे भाई ग्यालो थोण्डुप से मिले और कहा कि वह तिब्बतियों के साथ स्वतंत्रता की मॉग छोड़कर किसी भी विषय पर बातचीत करने को तैयार हैं। देंग ने निर्वासित तिब्बतियों को तिब्बत जाकर स्वंय तिब्बत का वास्तविक हाल देखने का निमंत्रण दिया।

अगस्त 1979

परमपावन दलाईलामा ने प्रथम तथ्य खोजी प्रतिनिधिमंडल तिब्बत भेजा।

मई 1980

द्वितीय तथ्य खोजी प्रतिनिधिमंडल तिब्बत गया।

जुलाई 1980

तीसरे तथ्य खोजी प्रतिनिधिमंडल की तिब्बत यात्रा

सितम्बर 1980

परमपावन दलाईलामा जी ने निर्वासित तिब्बती समुदाय से 50 प्रशिक्षित शिक्षकों को तिब्बत में शिक्षा के विकास में सहयोग के लिये भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने चीन सरकार और तिब्बतियों के बीच विश्वास कायम करने के उदेश्य से ल्हासा में सम्पर्क कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव रखा। चीन ने इन दोनों प्रस्तावों को यह कहकर टाल दिया कि इसे कुछ समय के लिये अभी स्थगित करते हैं।

जुलाई 1981

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री हू याओबांग ने तिब्बती प्रस्तावों के जवाब में ''दलाई लामा के प्रति चीन का पांच सूत्री नीति'' पेश की। दलाई लामा और उनके अनुयायियों की तिब्बत वापिस आने पर बल देते हुए कहा कि दलाई लामा के पास वही राजनीतिक अधिकार और रहन सहन की सुविधाएं मिलेंगी जैसी 1959 से पहले थीं। न तो वह तिब्बत में रहेंगे और न ही कोई पद पर रहेंगे। लेकिन वह समय-समय पर तिब्बत जा सकते हैं। उनके अनुयायियों को अपनी रोज़ी-रोटी के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिये। यह सब उन्हें पहले से अच्छा मिलेगा।

अप्रैल 1982

तीन सदस्यीय तिब्बती प्रतिनिधिमंडल चीनी नेताओं के साथ बातचीत की संभावनाएं खोजने के लिये बीजिंग गया। चीनी नेता उन्हें दुराग्रही रूख के साथ मिले।

अक्तूबर 1984

एक और दौर की बातचीत के लिये तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीजिंग गया। इस बार भी समझौते की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई।

सितम्बर 1987

अमेरिकी कांग्रेस के मानवाधिकार समूह को संबोधित करते हुये परमपावन दलाई लामा ने तिब्बत के लिये पांच सूत्री शांति प्रस्ताव की घोषणा की जिसमें उन्होंने तिब्बत के भविष्य पर गम्भीर वार्ता शुरू करने की बात कही।

जून 1988

स्ट्रासबर्ग मे यूरोपीय संसद में बोलते हुये दलाई लामा जी ने पांच सूत्री प्रस्ताव की व्याख्या की और तिब्बत के सभी तीन प्रातों के लिये स्वशासी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। परमपावन जी ने कहा कि यह व्यवस्था चीनी गणराज्य के साथ मिलकर होगी और तिब्बत की विदेश नीति और सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन सरकार के पास रहेगी।

सितम्बर 1988

बीजिंग सरकार ने तिब्बतियों के साथ समझौता करने की इच्छा जतायी और कहा कि दलाई लामा समझौते के लिये स्थान और समय का चुनाव कर सकते हैं।

अक्तूबर 1988

बीजिंग सरकार की इस उद्घोषणा का स्वागत करते हुये धर्मशाला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनवरी 1989 में जेनेवा में वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव किया। इस वक्तव्य में तिब्बत वार्ता प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नामों की भी घोषणा की गई। इसमें निर्वासित सरकार के छः पदाधिकारी और डच वकील माईकल वॉन वाल्ट कानूनी सलाहकार के रूप शामिल थे।

नवंबर 1988

चीन सरकार अपने पूर्व के कठोर रूख पर लौट आई। उसने कहा कि स्ट्रासबर्ग प्रस्ताव वार्ता का आधार नहीं हो सकता। चीन ने बहुत सारी शर्ते रखते हुये कहा कि बीजिंग, हांगकांग या चीन सरकार का विदेशो में स्थित कोई कार्यालय वार्ता का स्थान हो

सकता है। वर्तमान तिब्बती प्रतिनिधिमंडल उसको स्वीकार्य नहीं हो सकते क्योंकि इसके सभी सदस्य 'विभाजनकारी गतिविधियों' में सम्मिलित रहे हैं। तिब्बती समूह में कोई भी विदेशी शामिल नहीं होगा और वह (चीनी सरकार) परमपावन दलाई लामा या उनके विश्वस्त प्रतिनिधि, जैसे ग्यालो थोण्डुप, से सीधे बातचीत के लिए इच्छुक हैं।

दिसम्बर 1988

निर्वासित तिब्बत सरकार प्रतिनिधिमंडल में श्री ग्यालो दोण्डुप को शामिल करने पर सहमत हो गयी परन्तु अन्य शर्तों पर कायम रही।

अप्रैल 1989

बीजिंग द्वारा रखे गये शर्तो पर आगे विचार विमर्श के लिये धर्मशाला से हांग-कांग मिशन भेजने का प्रस्ताव रखा गया। मिशन ने हांग-कांग को प्रारम्भिक बातचीत का स्थान रखना स्वीकार कर लिया लेकिन उसके जल्द बाद चीन ने वार्ता में कोई दिलचस्पी नही दिखायी।

अक्तूबर 1991

परमपावन दलाई लामा ने बीजिंग के लिये एक नया प्रस्ताव रखा। येल विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में उन्होंने तिब्बत जाकर चीनी उच्च अधिकारियों के साथ वहां की वास्तविक स्थिति का मूल्याकंन करने की इच्छा जतायी।

दिसम्बर 1991

परमपावन दलाई लामा ने चीनी राष्ट्रपति ली पेंग के अगामी दिल्ली दौरे के अवसर पर मिलने की इच्छा जतायी।

जनवरी 1992

दलाई लामा जी के प्रस्ताव पर बींजिंग द्वारा लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से इन्कार करने पर निर्वासित तिब्बती संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जबतक चीनी नेतृत्व के रुख में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं होता है तब तक वार्ता के लिये कोई नई पहल नहीं शुरू करनी चाहिये।

अप्रैल 1992

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने ग्यालो थोण्डुप को वार्ता के लिए चीन आने का निमंत्रण दिया। चीनी दूतावास से कहा गया कि पहले चीन सरकार का रूख कड़ा था लेकिन अगर तिब्बती वास्तविकता अपनाने के लिये तैयार हैं तब वे लोग भी लचीला रूख अपनाने को तैयार हैं।

जून 1992

थोण्डुप दलाई लामा जी की अनुमति प्राप्त कर चीन गये लेकिन चीनी नेतृत्व ने तिब्बत के प्रति वही पुराना कठोर रुख दुहराया तथा दलाई लामा जी के विरूद्ध गंभीर आरोप भी लगाए।

जून 1993

श्री थोण्डुप के साथ वार्ता के दौरान चीनी नेतृत्व द्वारा उठायी गयी गलतफहमियों को दूर करने के लिये धर्मशाला से दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन गया। यह प्रतिनिधिमंडल परमपावन दलाई लामा जी की ओर से श्री देंग शियाओ पिंग ओर जियांग जेमिन को संबोधित १३ सूत्रीय ज्ञापन भी ले गया। ज्ञापन में दलाई लामा जी ने शांतिपूर्ण वार्ता के रास्ते तिब्बत समस्या के समाधान के लिए किये गये अपने प्रयासों का सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत करते हुये कहा कि "यदि हम तिब्बती अपने मौलिक अधिकारों को अपनी संतुष्टि के अनुसार प्राप्त कर लेते हैं तो हम चीनियों के साथ रहने के संभव फायदे को समझने में अक्षम नहीं होंगे। इसी वर्ष चीन ने धर्मशाला के साथ संचार के सभी औपचारिक रास्ते बंद कर दिये। अनौपचारिक एंव अर्द्ध-शासकीय माध्यम निरंतर खुले रहे।

जून 1998

बेजिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को बेजिंग में संबोधित करते हुये चीनी राष्ट्रपति जियांग ज़ेमिन ने कहा कि यदि दलाई लामा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते हैं कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग हैं और ताईवान को चीन के क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हैं, तब वे तिब्बतियों के साथ वार्ता के लिये इच्छुक होंगें।

मार्च 1999

10 मार्च को तिब्बत जनक्रांति दिवस के वार्षिक वक्तव्य में परमपावन दलाई लामा ने घोषणा की कि चीन ने उनके साथ वार्ता करने के लिये अपने रुख को कड़ा कर दिया है।

सितम्बर 2002

श्री लोडी ग्यालत्सेन ग्यारी और केलसांग ग्यालत्सेन के नेतृत्व में चार-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल फिर से संबंध स्थपित करने के लिये चीन और तिब्बत गया। धर्मशाला ने चीनी सरकार के सकारात्मक रुख का स्वागत किया।

मई 2003

श्री लोडी ग्यालत्सेन ग्यारी और केलसांग ग्यालत्सेन के नेतृत्व में दूसरी बार प्रतिनिधिमंडल चीन और तिब्बत गया।

तिब्बत

स्वायत्तता का कालक्रम से विवरण और तथ्य

तिब्बत में तीन क्षेत्र ऊत्सांग, खम और आम्दो समाहित हैं। 'तिब्बत स्वायत क्षेत्र' को पूरा तिब्बत नहीं समझ लेना चाहिये। चीनी मान्यता प्राप्त 'तिब्बत स्वायत क्षेत्र' सम्पूर्ण तिब्बत का आधे से भी कम भाग है। इसमें सम्पूर्ण तिब्बत की जनसंख्या की केवल एक-तिहाई ही रहती है।

तिब्बत भौगालिक क्षेत्र

तिब्बत का क्षेत्रफल ऊत्सांग, खम और आम्दो सहित 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। चीनी सरकार द्वारा घोषित तिब्बत स्वायत क्षेत्र का क्षेत्रफल सिर्फ 12 लाख वर्ग किलोमीटर है जिसमें केवल ऊत्सांग एंव खम का बहुत छोटा भाग सम्मिलित है। तिब्बत का बहुत बड़ा भाग तिब्बत स्वायत क्षेत्र के बाहर है।

प्रशासन

चीनी आधिपत्य के अधीन तिब्बत निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों मे बंटा हुआ है :

(क) तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र

(ख) छिंघाई प्रान्त

(ग) गांसु प्रान्त में टियांसु तिब्बती स्वायत्तशासी स्थानीय प्रशासनिक खण्ड तथा गन्नन तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र।

(घ) आबा तिब्बती–छयांग स्वात्तशासी प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र तथा मीलि तिब्बती स्वातशासी स्थानिय प्रशासनिक खण्ड जो कि सिचुआन प्रान्त में स्थित हैं।

(च) युन्नान प्रान्त में देचेन तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र

जनसख्यां

तिब्बत में तिब्बतियों की जनसंख्या 60 लाख है जिसमें से 20.9 लाख लोग चीन द्वारा

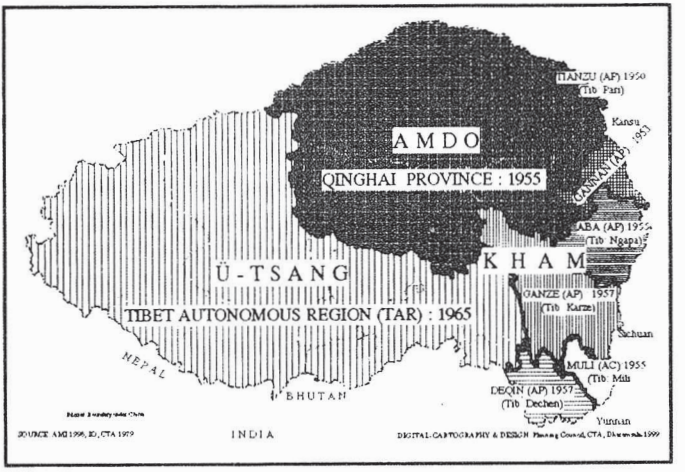

घोषित तिब्बत स्वायत क्षेत्र मे रहते हैं। अन्य लोग इस क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण तिब्बत में फैले हुये हैं।

तिब्बत पर भारत का रूख

वर्ष

1954: भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता । इसके दस्तावेज़ो में तिब्बत को चीन का तिब्बती क्षेत्र शब्दों में व्यक्त किया गया।

1955: चीनी गणराज्य द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के निर्धारण के लिये समिति का गठन

1958: भारत ने कहा "तिब्बत क्षेत्र चीनी गणराज्य का हिस्सा है।"

1965: चीनी गणराज्य द्वारा 'तिब्बत स्वायत क्षेत्र' की औपचारिक स्थापना

1988: श्री राजीव गांधी चीन गये और कहा कि "तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र है।

1993: श्री पी०वी नरसिंहराव चीन गये और कहा कि "तिब्बत चीन का स्वायत क्षेत्र है।"

2003: श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गये और तिब्बत स्वायत क्षेत्र को चीनी गणराज्य के हिस्से के रूप में मान्यता दी।

NOTES

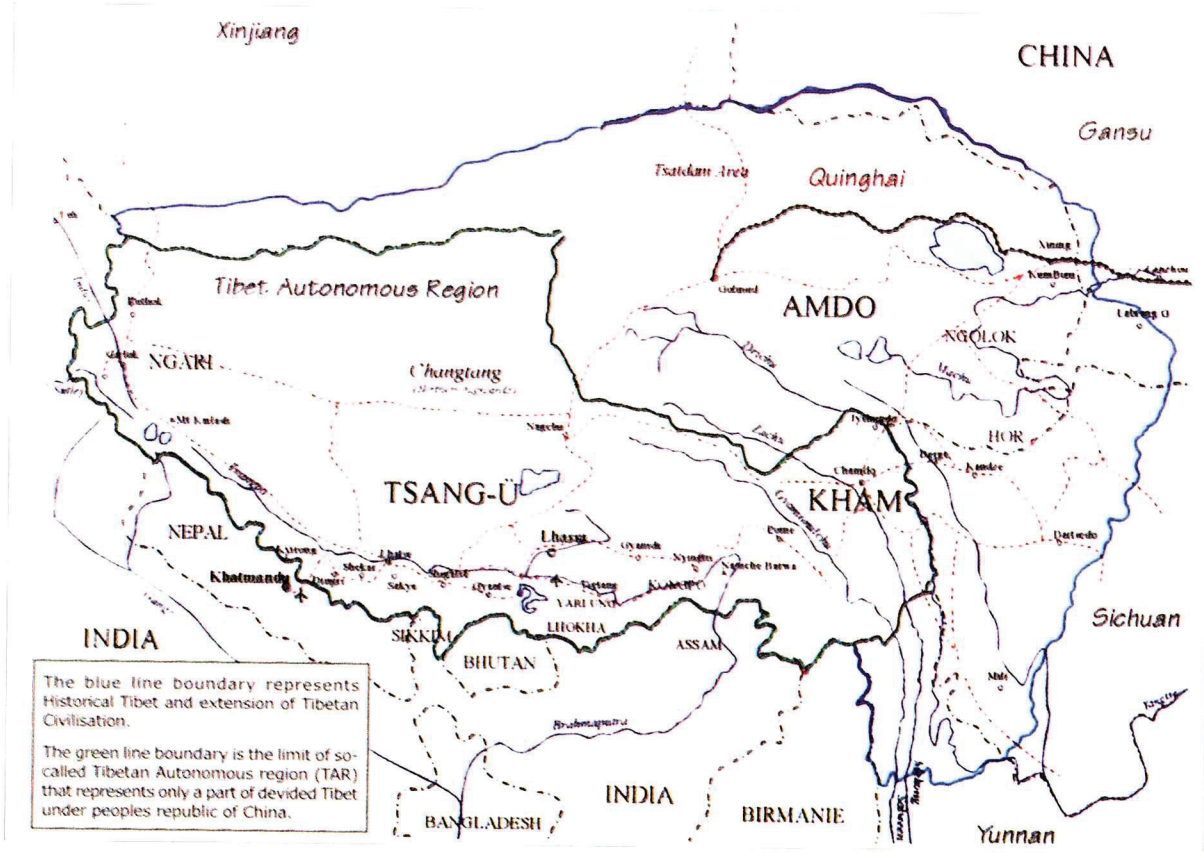
Xinjiang
CHINA
Gansu
Tsaidam Area
Quinghai
Tibet Autonomous Region
AMDO
NGOLOK
NGARI
Changtang
HOR
TSANG-Ü
KHAM
NEPAL
Khatmandu
INDIA
SIKKIM
BHUTAN
LHOKHA
ASSAM
Sichuan
The blue line boundary represents Historical Tibet and extension of Tibetan Civilisation.
The green line boundary is the limit of so-called Tibetan Autonomous region (TAR) that represents only a part of devided Tibet under peoples republic of China.
BANGLADESH
INDIA
BIRMANIE
Yunnan

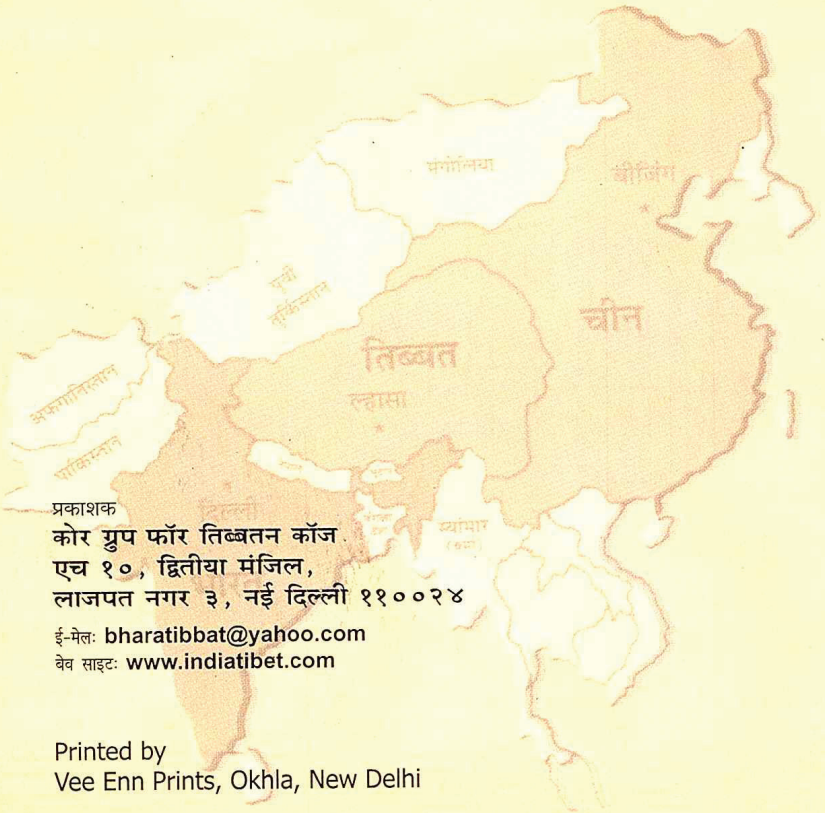

प्रकाशक
कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज
एच १०, द्वितीया मंजिल,
लाजपत नगर ३, नई दिल्ली ११००२४
ई-मेलः **bharatibbat@yahoo.com**
वेब साइटः **www.indiatibet.com**

Printed by
Vee Enn Prints, Okhla, New Delhi